



अग्रभारत

www.agrabharat.in



नई सोच का अखबार

दैनिक हिन्दी समाचार पत्र

वर्ष: 19

अंक: 94

आगरा, शनिवार 19 सितम्बर 2026

पृष्ठ: 8 मूल्य: 2.00 ₹.

प्रधानमंत्री की ‘चिंतन बैठक’ से कैबिनेट फेरबदल की अटकलें तेज

नई दिल्ली, (ए)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह केंद्रीय मंत्रियों के साथ दो दिवसीय विशेष ‘चिंतन बैठक’ करेंगे। यह बैठक 23 और 24 सितंबर को होगी, जिसे सरकार के कामकाज, नीतियों के क्रियान्वयन और भविष्य की प्राथमिकताओं को लेकर बेहद अहम माना जा रहा है। बैठक की टाइमिंग को देखते हुए राजनीतिक गलियारों में कैबिनेट फेरबदल की अटकलों ने भी जोर पकड़ लिया है, हालांकि सरकार की ओर से फेरबदल को लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। इस दौरान केंद्रीय मंत्रियों के साथ सरकार के कामकाज की गहन समीक्षा की जाएगी, जिसमें खास तौर पर नीतियों को जमीन पर लागू करने की गति, सरकारी योजनाओं की प्रगति, मंत्रालयों के बीच बेहतर तालमेल और आम लोगों तक सरकारी सेवाओं की पहुंच जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो सकती है।

सूत्रों के मुताबिक, यह बैठक सामान्य कैबिनेट बैठक से अलग तरीके की होगी। इसमें मंत्रियों को अलग-अलग समूहों में बांटकर विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श कराया जा सकता है। रिपोर्टों के अनुसार, ऐसे कई समूह बनाए गए हैं, जिनमें मंत्री शासन व्यवस्था, संवाद, सुधार और सरकार के कामकाज को और प्रभावी बनाने जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बैठक में कुछ मंत्रालयों की ओर से अपने कामकाज और



उपलब्धियों को लेकर प्रस्तुतीकरण भी दिए जाने की संभावना है। सरकार की मौजूदा योजनाओं की स्थिति, अब तक हासिल किए गए परिणाम और आने वाले महीनों के लिए प्राथमिकताओं पर विस्तृत चर्चा हो सकती है। इस चिंतन बैठक का एक बड़ा उद्देश्य नीति निर्माण की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और

परिणामदायी बनाना है। सरकार यह देखना चाहती है कि नीतियां तैयार होने के बाद उनका वास्तविक असर जमीन पर कितना दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही समय प्रबंधन, मंत्रालयों के बीच समन्वय, योजनाओं की निगरानी और जनसेवा की डिलीवरी को बेहतर बनाने के उपायों पर भी चर्चा होने की संभावना

है, यानी बैठक में केवल बीते समय के कामकाज की समीक्षा नहीं होगी, बल्कि आने वाले महीनों के लिए सरकार की कार्ययोजना पर भी मंथन होगा।

यह बैठक ऐसे समय हो रही है जब केंद्र की मौजूदा सरकार अपने तीसरे कार्यकाल के लगभग मध्य में पहुंच चुकी है। ऐसे में अगले चरण के लिए प्राथमिकताएं तय करने और मंत्रालयों के कामकाज की दिशा को लेकर यह बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सरकार के स्तर पर इसे मुख्य रूप से शासन और नीतियों की समीक्षा से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल, पिछले कुछ समय से केंद्र में संभावित कैबिनेट फेरबदल को लेकर राजनीतिक अटकलें चल रही हैं और अब 23-24 सितंबर को सभी केंद्रीय मंत्रियों के साथ होने वाली विस्तृत बैठक ने इन चर्चाओं को और बढ़ा दिया है। कुछ रिपोर्टों में इस बैठक को संभावित फेरबदल की तैयारियों के संदर्भ में भी देखा जा रहा है। कैबिनेट फेरबदल की चर्चा पहले से ही चल रही है।

गठबंधन में दरार? ममता और डीएमके से अलग तीसरा मोर्चा बनाएंगे?

नई दिल्ली (ए)। 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले भारत की राजनीति में बड़ी हलचल होने के आसार दिख रहे हैं। इसके संकेत हाल ही में हुई कुछ बैठकों से मिल रहे हैं, जहां द्रविड़ मुन्नेत्र कड़मम (डीएमके) की सांसद कनिमोई ने पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की है। खबरें हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बगैर कांग्रेस के एक क्षेत्रीय दलों का गठबंधन तैयार करने की योजना बनाई जा रही है, हालांकि इसे लेकर औपचारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है। कनिमोई और ममता बनर्जी ने गुरुवार को कोलकाता में मुलाकात की। कालीघाट स्थित पूर्व मुख्यमंत्री के आवास पर हुई इस बैठक में किन मुद्दों पर बात की गई, इसे लेकर स्थिति साफ नहीं हो पाई है। इससे पहले, डीएमके नेता ने शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) से लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले से भी मुलाकात की थी। कहा जा रहा है कि वह जल्द ही आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख अरविंद



केजरीवाल से भी मिल सकती हैं। इन मुलाकातों को एक तीसरे मोर्चे की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है।

डीएमके के एक नेता ने कहा है कि, हम बगैर कांग्रेस के एक तीसरे मोर्चे की संभावनाएं तलाश रहे हैं। इधर, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के एक सांसद ने बातचीत में बताया कि, ममता बनर्जी के डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। वह गैर-एनडीए पार्टियों के साथ भी अच्छे रिश्ते बनाए रखती हैं और इंडिया, अच्छे रिश्ते बनाए रखती हैं और इंडिया, अच्छे रिश्ते के करीब हैं जो कांग्रेस समर्थक नहीं हैं। आज की बातचीत सिर्फ उनके और कनिमोई के बीच हुई। इसके अलावा कुछ भी कहना सिर्फ अटकलें लगाना होगा। यह

सवाल उठ रहा है कि क्या डीएमके की तरह ममता बनर्जी भी कांग्रेस से नाराज हैं। तमिलनाडु की राजनीति में लंबे समय तक कांग्रेस और डीएमके एक साथ रहे और विधानसभा व लोकसभा चुनाव साथ लड़े, लेकिन 2026 चुनाव के बाद स्थिति बदल गई। कांग्रेस राज्य के सबसे बड़े दल तमिलनाडु वेन्नी कड़मम से जा मिली और पुराने साथी डीएमके को छोड़ दिया। नतीजा यह हुआ कि डीएमके ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और इंडिया गठबंधन से भी दूरी बना ली। वहीं, ममता बनर्जी की नाराजगी की एक वजह सीट शेयरिंग हो सकती है। खबरें थीं कि पश्चिम बंगाल की दो सीटों पर होने वाले आगामी उपचुनाव को लेकर ममता ने कांग्रेस से मदद मांगी थी, जिसे कांग्रेस ने ठुकरा दिया। हालांकि, टीएमसी नेता इससे इनकार कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस खुलकर इसे स्वीकार कर रही है। खबरें थीं कि पूर्व मुख्यमंत्री ने कांग्रेस से रेजिनगर सीट पर समर्थन मांगा था और नंदीग्राम सीट छोड़ने की पेशकश की थी।

मेटा को प्लेटफॉर्म द्वारा वितरित कंटेंट के लिए ज्यादा जिम्मेदारी लेनी होगी

नई दिल्ली, (ए)। सोशल मीडिया क्षेत्र की दिग्गज कंपनी मेटा के भारत में संचालित प्लेटफॉर्मों को अब केवल इंटरनेट मध्यस्थ नहीं माना जा सकता। सरकारी सूत्रों के मुताबिक कंपनी ने अपने एग्लोरिदम के जरिये कंटेंट के प्रसार, वितरण और उसकी दृश्यता को सक्रिय रूप से तय करने के लिए पैसे लिए जाते हैं, इसलिए उसे सेवा प्रदाता के तौर पर देखा जाना चाहिए। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि कंपनी को अब अपने प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और थ्रेड्स पर उपयोगकर्ताओं द्वारा साझा और प्लेटफॉर्मों द्वारा वितरित किए जाने वाले कंटेंट के लिए ज्यादा जिम्मेदारी लेनी होगी। अधिकारी ने कहा कि मेटा की भूमिका अब केवल उपयोगकर्ताओं द्वारा साझा किए गए कंटेंट को होस्ट करने या उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने तक सीमित नहीं रह गई है।



उसे ईमेल किया गया लेकिन खबर लिखे जाने तक जवाब नहीं आया। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और थ्रेड्स की संचालक कंपनी मेटा को कानूनी संरक्षण हासिल नहीं है। इसलिए इन प्लेटफॉर्मों पर साझा किए गए

उसे ईमेल किया गया लेकिन खबर लिखे जाने तक जवाब नहीं आया। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और थ्रेड्स की संचालक कंपनी मेटा को कानूनी संरक्षण हासिल नहीं है। इसलिए इन प्लेटफॉर्मों पर साझा किए गए

दिल्ली में 16 साल की लड़की का गैंगरेप कर हत्या

नई दिल्ली, (ए)। दिल्ली में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 16 साल की एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप के बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस जघन्य अपराध में चार लड़के शामिल हैं, जिनमें तीन नाबालिग हैं और एक 19 साल का युवक है। यह मामला रविवार को तब सामने आया जब बाहरी दिल्ली के स्वरूप नगर के एक खेत में स्थानीय लोगों ने लड़की के शव-विश्रुत शव को कुत्तों और अन्य जानवरों को नोचते हुए देखा। पुलिस ने रात भर चले तलाशी अभियान के बाद सभी चारों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है।

पुलिस को रविवार सुबह कुशक रोड के पास खेत में शव मिलने की सूचना मिली। शव बुरी तरह क्षत-विक्षत था, दाहिना हाथ गायब था और सड़ने-गलने के कारण चेहरा व पेट पूरी तरह बिगड़ चुके थे। प्रारंभिक जांच में लड़की की पहचान करना मुश्किल था। मेडिकल रिपोर्ट में गैंगरेप की पुष्टि हुई और उसके शरीर पर चाकू से आठ से अधिक वार के निशान मिले, जिससे यह साफ था कि उसकी हत्या की गई थी। इसके बाद पुलिस ने हत्या, गैंगरेप और सबूत मिटाने का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। शुरुआती पहचान के अभाव में पुलिस ने शव फेंकने के आसपास की गहन जांच शुरू की। इलाके के 50 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने पर घटनास्थल के पास अपराध के समय एक टेम्पो दिखा। हालांकि नंबर स्पष्ट नहीं था, स्थानीय पूछताछ और फुटेज विश्लेषण से पुलिस टेम्पो तक पहुंची। ड्राइवर से पूछताछ पर पता चला कि उसका 17 वर्षीय छोटा भाई अक्सर गाड़ी चलाता था। फुटेज में टेम्पो के अंदर चार लड़के दिखे, जिनकी पहचान हुई लेकिन वे घरों से भाग गए थे। सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय जानकारी के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के भागने का रास्ता पता लगाया। मंगलवार रात चले तलाशी अभियान के बाद स्वरूप नगर की खड्डा कॉलोनी से टेम्पो और उसके ड्राइवर को बरामद किया गया, जिसके बाद चारों आरोपी पकड़े गए। पुलिस ने उनकी पहचान 19 वर्षीय शिवम गणेश और तीन नाबालिगों (17, 16 वर्ष) के रूप में की है। पुलिस ने अपराध में इस्तेमाल किए गए दो चाकू और आरोपियों के कपड़े बरामद किए हैं। कम से कम तीन आरोपियों ने पीड़िता के साथ रेप करने की बात कबूल कर ली है। जांचकर्ताओं के अनुसार, नाबालिग लड़की शुक्रवार रात को 17 वर्षीय आरोपी लड़के से मिलने गई थी। उस लड़के ने सबसे पहले उसके साथ रेप किया, जिसके बाद लड़की ने पुलिस को शिकायत करने की धमकी दी। इस पर उसने अपने दोस्तों को बुला लिया, जिन्होंने लड़की को काबू कर सामूहिक दुष्कर्म किया। सभी आरोपी शराब के नशे में थे। रेप के बाद उन्होंने लड़की को एक खेत में ले जाकर छह से अधिक बार चाकू मारा और शव को पतों व कीचड़ के नीचे छिपाने की कोशिश कर टेम्पो में भाग गए। मुतका स्कूल छोड़ चुकी थी और अपने माता-पिता की मदद के लिए नौकरी ढूँढ रही थी।

सरकारी जमीन के इस्तेमाल के लिए कांग्रेस से मांगे 4 लाख अतिरिक्त

नई दिल्ली, (ए)। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के इंदौर में होने वाले ‘छत्रों की गुंज’ कार्यक्रम को लेकर विवाद बढ़ गया है। इंदौर विकास प्राधिकरण (आईडीए) ने कार्यक्रम के लिए इस्तेमाल की जा रही सरकारी जमीन के एवज में कांग्रेस से 4 लाख 3 हजार 270 रुपये की अतिरिक्त राशि जमा करने को कहा है। प्राधिकरण के मुताबिक, कांग्रेस ने तय अवधि से पहले ही जमीन के एक हिस्से का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। राहुल गांधी का ‘छत्रों की गुंज’ कार्यक्रम 19 सितंबर को इंदौर में प्रस्तावित है। कांग्रेस ने इसके लिए इंदौर के रीजनल पार्क के पास स्थित आईडीए की करीब 12,000 वर्ग मीटर जमीन अस्थायी तौर पर ली है। रिपोर्ट के मुताबिक, आईडीए ने यह जमीन इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी को 17 सितंबर से 19 सितंबर तक के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी। पार्टी ने इस तीन दिन की अवधि के लिए पहले ही 10.08 लाख रुपये का भुगतान कर दिया था।

आईडीए के मुताबिक, स्थल के निरीक्षण के दौरान सामने आया कि जमीन के करीब 4,800 वर्ग मीटर हिस्से का इस्तेमाल 14 सितंबर से ही शुरू कर दिया गया था, जबकि अनुमति 17 सितंबर से थी। प्राधिकरण ने 16 सितंबर को इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे को भेजे पत्र में स्पष्ट किया कि जमीन का आवंटन केवल 17 से 19 सितंबर तक के लिए किया गया था। पहले के पत्राचार में भी स्पष्ट किया गया था।

हूती हमलों और संकट के बीच भारत के लिए सोहार पोर्ट खोलेगा ओमान!

नई दिल्ली, (ए)। हूतियों के कहर से पश्चिम एशिया में संकट और पेचीदा हो गया है। होर्मुज पूरी तरह से ब्लॉक है। अमेरिका और ईरान की लड़ाई का दापरा बढ़ चुका है। ऐसे में ओमान ने भारत को अपने सोहार पोर्ट को लेकर ऑफर दिया है, जिससे न केवल फारस की खाड़ी से तेल लाना आसान होगा, बल्कि हमारे लिए अमेरिका, खाड़ी देशों और यहां तक कि अफ्रीका तक भविष्य में भी व्यापार करना बेहद आसान हो जाएगा।

मोडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत-ओमान कंफ्रेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को लेकर ओमान के राजदूत ईसा सालेह अब्दुल्ला सालेह अलशिबानी ओमानी दूतावास की ओर से एक प्रमोशनल इवेंट की शुरुआत में ही कह चुके हैं। मैं समझता हूँ कि सोहार और ओमान के ज्यादातर पोर्ट ओमान, मध्य-पूर्व और इससे विशाल क्षेत्र के लिए भी भारत के मैनुफैक्चरिंग विस्तार के लिए विशाल गेटवे बनते जा रहे हैं। ओमान के सोहार पोर्ट को लेकर फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के डीजी और सीईओ डॉ. अजय सहाय का कहना है, हमारे बढ़ते व्यापार के लिए सोहार पोर्ट का रणनीतिक स्थान अहम है। क्योंकि सोहार में पोर्ट के अलावा फ्री ट्रेड ज़ोन भी है, जहां हम इन्वेस्टमेंट और मैनुफैक्चरिंग की भी सोच सकते हैं। उन्होंने सोहार पोर्ट के पास फ्री ट्रेड



जोन में वेयरहाउस बनाने की संभावना भी जताई, जिससे पूर्वी अफ्रीका और पहले ओमान ने भारत को दुष्कर्म और सलालाह बंदरगाहों का ऑफर दिया था, लेकिन उत्तरपूर्वी ओमान में होने की वजह से सोहार भारत के लिए ज्यादा उपयुक्त है। यह यूएई के महत्वपूर्ण तेल पाइपलाइनों और पूर्वी सऊदी अरब से भी सटा हुआ है, जिस तरह से हूतियों ने ईरान-अमेरिका युद्ध में खुद को शामिल किया है, उससे यूएई के बंदरगाहों तक पहुंचने का जोखिम भी बढ़ गया है और रिपोर्ट है कि लाल सागर में अहम पाइप लाइनों को ड्रेन से निशाना बनाए जाने के बाद सऊदी अरब भी सोहार पोर्ट से जहाजों के जरिए ही कच्चा तेल भेजने को प्रार्थमिकता दे रहा है।

अमेरिका भारत पर 100 फीसदी टैरिफ लगाया तो द्विपक्षीय संबंधों पर पड़ेगा असर

भारत ने साफ कर दिया अपनी आबादी की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखा जाएगा

नई दिल्ली, (ए)। रूस के नाम पर भारत पर 100 फीसदी टैरिफ लगाने वाले अमेरिकी बिल पर सरकार ने जवाब दे दिया है। भारत ने साफ कर दिया है कि अपनी आबादी की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखा जाएगा। साथ ही चेतावनी है कि इसका असर द्विपक्षीय संबंधों पर भी पड़ सकता है। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा में उस बिल को अनुमति दे दी गई, जो भारत समेत कई देशों पर 100 फीसदी टैरिफ लगाने की ताकत अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को देता है। विदेश मंत्रालय ने लिंडसे ओ ग्राहम संश्लेषित रूस एंड ईरान एक्ट एक्ट 2026 को लेकर कहा है कि इससे जुड़े घटनाक्रमों पर नजर रखी जा रही है। खास बात है कि अमेरिका पहले भी भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगा चुका है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि जैसा कि पहले भी कई बार कहा गया है, भारत अपने 1.4 अरब लोगों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। वह अलग-अलग स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करेगा और बदलते बाजार के हालात के आधार पर ऐसा करना जारी रखेगा। हाल में कई अमेरिकी अधिकारियों के साथ इस मुद्दे पर उच्च स्तर पर चर्चा हुई है।

भारत ने यह बात बहुत साफतौर से रखी है कि इसका असर सिर्फ हमारे आपसी रिश्तों पर ही नहीं, बल्कि वैश्विक ऊर्जा बाजार पर भी पड़ सकता



है। मंत्रालय ने कहा कि भारत ने साफ कर दिया है कि वह अपने कारोबारी और आर्थिक हितों को बचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सरकार भारत के कारोबारी और औद्योगिक समूहों के साथ घटनाक्रमों से पड़ने वाले असर को कम किया जा सके। भारत और चीन समेत कई देशों पर 100 फीसदी टैरिफ लगाने का समर्थन करने वाले इस बिल ने आखिरी बाधा भी पार कर ली है। अभी इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने बाकी हैं। विधेयक के पक्ष में 203 रिपब्लिकन, 58 डेमोक्रेट और एक निर्दलीय सांसद ने मतदान किया। वहीं, रिपब्लिकन पार्टी के सात और 152 डेमोक्रेट सांसदों ने इस विधेयक का विरोध किया। विधेयक में रूस के नेतृत्व और उसके ऊर्जा क्षेत्र पर प्रतिबंध लगाने के साथ-साथ उन जहाजों के छत्र बंदों पर भी प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है, जो मास्को को तेल

चुनाव आयोग ने टीएमसी का नाम और चिन्ह फ्रीज किया

कोलकाता (ए)। चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) को एक बड़ा झटका दिया है, जिसके तहत पार्टी के दोनों प्रतिद्वंद्वी धड़ों के लिए उसके नाम और चुनाव चिन्ह फूल और घास को फिलहाल फ्रीज कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब टीएमसी के दोनों में से कोई भी गुट आगामी उपचुनावों में इस चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। राज्य में नंदीग्राम और रजनीगर सीटों पर होने वाले उपचुनावों को देखते हुए आयोग ने दोनों धड़ों से अपनी पार्टी के लिए एन नाम और चुनाव चिन्ह सुझाने को कहा है। चुनाव आयोग ने अपने इस फैसले के लिए इलेक्शन सिंबल (रिजर्वेशन एंड एलॉटमेंट) ऑर्डर, 1968 के पैरा 15 को आधार बनाया है। यह आदेश राजनीतिक दलों की पहचान और उनके चुनाव चिन्हों के आवंटन को नियंत्रित करता है, विशेष रूप से पार्टी के भीतर विवाद की स्थिति में। पैरा 15 का मूल प्रावधान यह अधिकार देता है कि जब किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के दो या अधिक धड़े खुद को वही पार्टी बताते हैं, तो आयोग उपलब्ध तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने तथा संबंधित पक्षों को सुनने के बाद यह तय कर सकता है कि इनमें से कौन-सा धड़ा उस मान्यता प्राप्त पार्टी का प्रतिनिधित्व करता है या कोई भी नहीं। यह फैसला दोनों प्रतिद्वंद्वी धड़ों पर बाध्यकारी होता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी 1971 के सादिक अली बनाम चुनाव आयोग मामले में पैरा 15 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा था। मौजूदा मामले में, टीएमसी के दोनों धड़ों ने पार्टी के नाम और आरक्षित चुनाव चिन्ह फूल और घास पर अपना दावा पेश किया है। आयोग ने माना है कि उसके सामने दो प्रतिद्वंद्वी समूह हैं और विवाद पर पैरा 15 के तहत अंतिम फैसला अली बाकी है। चूंकि पश्चिम बंगाल में 6 अक्टूबर को उपचुनाव होने हैं और पैरा 15 के तहत पूरी सुनवाई और अंतिम फैसला करने में समय लग सकता है।

